THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Rajya Sabha as soon as it is received.

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति

2452. **श्री रामचन्द्र विकल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अनुमानत: कितनी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार श्रमिकों को कार्य सुलभ कराने के लिये कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) सातवीं योजना के डाक्यूमेंट के अनुसार, सातवीं योजना के आरम्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अनुमान 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 4.97 मिलियन लगाया गया है। इसका राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, सामान्य स्तर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कुल व्यक्तियों की तुलना में बेरोजगारों का प्रतिशत 1983 में किए गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें दौर से मिलता है, जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की पत्रिका अर्थात् "सर्वेक्षण वाल्यूम 9–संख्या 4 (अप्रैल, 1986) में प्रकाशित किया गया है। इस पर आधारित विभिन्न राज्यों में सीमान्त श्रमिकों सहित सामान्य स्तर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है (नीचे देखिये)

(ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के संदर्भ में चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 (अक्तूबर, 1986 तक) के दौरान उपयोग में लाई गई नकद निधियों और खाद्यान्नों तथा सृजित किए गए रोजगार को दर्शाने वाला विवरण–2 संलग्न है।

विवरण–1

सामान्य स्तर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष और उससे ऊपर के आयु के कुल व्यक्तियों में बेरोजगारों का प्रतिशत

अवधि : जनवरी–जून, 1983 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 38वां दौर)

राज्य	पुरुष	महिलाएं
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1.18	0.58
2. असम	1.51	0.25

1	2	3
3. बिहार	1.48	0.15
4. गुजरात	0.89	0.38
5. हरियाणा	1.72	0.07
6. हिमाचल प्रदेश	1.15	0.14
7. जम्मू तथा कश्मीर	0.62	0.16
8. कर्नाटक	0.63	0.28
9. केरल	6.93	3.96
10. मध्य प्रदेश	0.32	0.04
11. महाराष्ट्र	1.02	0.10
12. मणिपुर	0.48	—
13. मेघालय	0.48	—
14. नागालण्ड	—	—
15. उड़ीसा	1.19	0.31
16. पंजाब	1.85	1.00
17. राजस्थान	0.57	0.02
18. सिक्किम	1.18	—
19. तमिलनाडु	2.80	1.98
20. त्रिपुरा	0.47	2.91
21. उत्तर प्रदेश	0.94	0.04
22. पश्चिम बंगाल	2.39	0.54
23. अंण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.38	1.03
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—
25. चण्डीगढ़	2.47	—
26. दादरा तथा नगर हवेली	0.83	0.61
27. दिल्ली	3.72	—
28. गोवा दमन तथा दीव	2.25	1.25
29. लक्षद्वीप	—	—
30. मिजोरम	0.08	—
31. पांडिचेरी	0.97	0.51
अखिल भारत :	1.45	0.51

विवरण–2

1985–86 और 1986-87 (अक्तूबर, 1986 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद निधियों और खाद्यान्नों के उपयोग तथा रोजगार सृजन

	उपयोग की गई नकद निधियां (करोड़ रुपये में)	उपयोग किया गया खाद्यान्न (लाख मी० टन)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :			
वर्ष 1985–86 . . .	95.86	1.14	501.90
1986–87 (अक्तूबर, 1986 तक) . .	46.87	0.75	206.78
2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :			
वर्ष 1985–86 . . .	99.28	0.48	407.26
1986–87 (सितम्बर, 1986 तक) .	47.77	0.63	214.09

गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति

2453. **श्री संतोष बागड़ोदिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पेय जल की समस्या के समाधान के लिए एक नीति बनाई गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में भीलवाड़ा के जनजातीय क्षेत्रों के कतिपय गांवों में पीने का पानी खारा है, यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में पेय जल की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाई जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र में जल-पूर्ति की योजना अधूरी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): (क) सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना 20-सूत्री कार्यक्रम–1986 का सूत्र संख्या 7 है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड द्वारा 1984 में भीलवाड़ा जिले के भूगत जल संसाधन तथा विकास सम्भाव्यता पर तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जिले के अधिकांश भाग में भूमिगत जल की क्वालिटी अच्छी है और पेयजल तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है। सतही जलाशयों के आसपास के भूखण्डों में कलोराइड की मात्रा अधिक होती है । चूंकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए राजस्थान राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए योजनाएं बनायें और उन्हें निष्पादित करे। राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार भीलवाड़ा जिले में 1512 गांव हैं जिनमें से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की दृष्टि से 1117 गांवों का समस्याग्रस्त गावों